

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3690

जिसका उत्तर मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2014 को दिया जाना है

ऑटोमोटिव मिशन प्लान

3690. श्री डी. के. सुरेश:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2006-16 शुरू किया है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त प्लान के उद्देश्य क्या हैं;
- (ग) क्या कर्नाटक में रामनगर जिले सहित देश के कुछ क्षेत्र ऑटोमोटिव उद्योग के विकास के लिए समुचित अवसंरचना मौजूद है और यदि हां, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त क्षेत्र में ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्धेश्वर)**

(क) और (ख): सरकार ने भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के लिए विकास की उच्च दर और भारतीय बाजार की आकर्षकता को बनाए रखने के लिए तथा भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता में और वृद्धि करने के लिए ऑटोमोटिव मिशन प्लान (एएमपी) 2006-16 तैयार किया है। इस मिशन प्लान में भारतीय ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:-

"ऑटोमोबाइल्स और ऑटोकलपुर्जों के डिजाइन एवं विनिर्माण के लिए विश्व में एक पसंदीदा देश के रूप में उभरना और 10% से अधिक सकल घरेलू उत्पाद के साथ 145 बिलियन अमरिकी डॉलर के स्तर तक उत्पादन प्राप्त करना तथा वर्ष 2016 तक 25 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करना।"

(ग) और (घ): बुनियादी सुविधाओं तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चेन्नई-बैंगलोर, पूणे-औरंगाबाद, दिल्ली-एनसीआर और इन्दौर सहित देश में कई ऑटोमोटिव हब्स विकसित किए गए हैं। इसके अलावा, वर्तमान में पूरे देश में ऑटोमोबाइल उद्योग में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।
